श्री नरेश कुमार

अध्यक्ष

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

द्वारा

बजट भाषण

BUDGET SPEECH

By

SH. NARESH KUMAR

CHAIRPERSON

NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL

दिनॉक: 13 जनवरी, 2016

Dated: 13th January, 2016

बजट भाषण- 2016-17

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के माननीय सदस्यगण

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के माननीय सदस्यों, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं हमारे संगठन का आगामी वर्ष 2016-17 का बजट प्रस्तुत करने के लिए आज सुबह आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की शुरुआत 25 मार्च 1913 को इम्पीरियल दिल्ली कमेटी की स्थापना के साथ हुई थी। वर्ष 1916 में, यह नगरपालिका केवल उन श्रमिकों की स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरी कर रही थी, जो नई राजधानी के निर्माण में लगे थे। समय के साथ-साथ, नगरपालिका के कार्यों में कई गुना वृद्धि हुई है। एक सदी से अधिक समय से विद्यमान इस नगर निकाय ने एक संगठन का रूप ले लिया है, जो न केवल निवासियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने का दायित्व निभा रही है, बल्कि क्षेत्र को रहने योग्य और भरोसेमंद बनाने के लिए हमेशा सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करती है।

न.दि.न.परिषद् का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस राजधानी शहर में सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक, भारत का प्रशासनिक ढांचा स्थित है। अतः न.दि.न. परिषद का यह दायित्व है कि वह एक ऐसा शहर प्रदान करे जिसमें उसके नागरिक अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकें। एक ऐसे देश के लिए, जो दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने जा रहा है, यह जरूरी है कि उसकी राजधानी भी विश्व का सर्वोत्कृष्ट शहर हो।

इसे ध्यान में रखते हुए, परिषद ने निर्णय किया है कि न.दि.न.परिषद का लक्ष्य ''राजधानी शहर के लिए वैश्विक प्रतिमान (बेंचमार्क) बनना'' है। इस संदर्भ में मैं परिषद के समक्ष वार्षिक बजट 2016-17 प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. मैं वित्तीय अनुमान पहले प्रस्तुत करना चाहूँगा।

बजट अनुमान 2016-17 के लिए कुल प्राप्तियां ₹3458.33 करोड़ की हैं, जबकि संशोधित अनुमान 2015-16 में ₹3286.89 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2014-15 में कुल वास्तविक प्राप्तियां ₹3243.81 करोड़ थीं। बजट अनुमान 2016-17 में राजस्व प्राप्तियां ₹3041.59 करोड़ की है जबकि संशोधित अनुमान 2015-16 में ये ₹2890.71 करोड़ हैं, और 2014-15 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹2737.28 करोड़ की थीं। बजट अनुमान 2016-17 के लिए पूंजीगत प्राप्तियों के ₹416.74 करोड़ हैं, जबकि संशोधित अनुमान 2015-16 में ये ₹396.18 करोड़ हैं और वर्ष 2014-15 में वास्तविक पूंजीगत प्राप्तियां ₹506.53 करोड़ की थीं।

BUDGET SPEECH 2016-17

Esteemed Members of the New Delhi Municipal Council,

It is my privilege to stand before you this morning to present to you the budget for the forthcoming year of 2016-17 for our organization.

New Delhi Municipal Council started with the formation of the Imperial Delhi Committee on 25th March, 1913. In the year 1916, this municipality was discharging the responsibility to cater only to the sanitation requirements of the workers engaged in the construction of the new capital. With time, the functions of the municipality increased manifold. Being in existence for more than a century, this Civic Body has grown into an organization with the responsibility of not only providing civic services to the residents, but to make the area livable and sustainable, always laying stress on quality of service.

NDMC's key profile is that it houses the administrative setup of the country within the capital city of one of the fastest growing economy. NDMC thus has the responsibility to provide a city that will allow its citizens to achieve their aspirations. For a country poised to become one of the largest economies, nothing short of being the best capital city in the world would do justice.

Considering this, the Council has decided that the vision of NDMC will be “To become the Global Benchmark for a Capital City”. In this respect, I am presenting the Annual Budget 2016-17 before the Council:

1 I will present the financial projections first.

The total receipts for budget estimates 2016-17 are ₹3458.33 crore against ₹3286.89 crore provided in revised estimates 2015-16. The total actual receipts in 2014-15 were ₹3243.81 crore. The budget estimates 2016-17 for revenue receipts are ₹3041.59 crore against ₹2890.71 crore provided in revised estimates 2015-16 and actuals of ₹2737.28 crore in 2014-15. The budget estimates 2016-17 for capital receipts are ₹416.74 crore against ₹396.18 crore provided in revised estimates 2015-16 and actuals of ₹506.53 crore in 2014-15.

बजट अनुमान 2016-17 में कुल व्यय ₹3450.81 करोड़ है, जबकि संशोधित अनुमान 2015-16 में यह ₹3077.31 करोड़ हैं और 2014-15 में वास्तविक व्यय ₹3041.17 करोड़ का था। बजट अनुमान 2016-17 में राजस्व व्यय के लिए ₹3038.34 करोड़ रखे गए हैं, जो संशोधित अनुमान 2015-16 में ₹2885.38 करोड़ हैं और 2014-15 में वास्तविक राजस्व व्यय ₹2826.97 करोड़ था। बजट अनुमान 2016-17 के अनुसार पूंजीगत व्यय ₹412.47 करोड़ (जिसमें स्मार्ट परियोजनाओं के लिए ₹76 करोड़ शामिल हैं) आंका गया है, जो संशोधित अनुमान 2015-16 में ₹191.93 करोड़ (जिसमें स्मार्ट परियोजनाओं के लिए ₹11 करोड़ शामिल हैं) हैं, जबकि 2014-15 का वास्तविक पूंजीगत व्यय ₹214.20 करोड़ था।

स्मार्ट सिटी मिशन के प्रथम चरण में चुने जाने के बाद, न.दि.न.परिषद् ने स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे चरण के लिए स्मार्ट सिटी प्रस्ताव 15 दिसंबर, 2015 को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को भेजा है। यदि न.दि.न.परिषद् को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुना जाता है, तो उसे शहरी विकास मंत्रालय से प्रथम किश्त के रूप में ₹194 करोड़ का सह-अनुदान मिलने की संभावना है, जिसमें न.दि.न.परिषद् को भी समान योगदान करना होगा।

2. स्मार्ट चिकित्सा सेवाएं

न.दि.न.परिषद् स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में निरंतर सुधार कर रही है ताकि इसके नागरिक परिषद के दो अस्पतालों, दो पोली-क्लिनिकों और 38 डिस्पेन्सरियों के जरिए उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें। मैं 2016-17 में चिकित्सा सेवाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसमें प्रमुख उपायों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(i) सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली

विद्यमान सार्वजनिक चिकित्सा केंद्रों के क्लाउड-आधारित एकीकरण के जरिए स्वास्थ्य प्रणाली की सक्षमता और प्रभावकारिता में सुधार लाने का प्रस्ताव है। इससे एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पहुंच बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्राप्त करने में लगने वाले समय में कमी लाने में मदद मिलेगी, जिसका समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को विशेष लाभ होगा। न.दि.न.परिषद् ने एनआईसी की क्लाउड-आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) को शुरू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, जो किसी सरकारी व्यवस्था में देश में इस तरह की पहली प्रणाली होगी। इस साफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के माड्यूल शामिल हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल सेवा को अधिक सक्षम बनाते हैं इनमें रोगी पंजीकरण, क्लिनिक, आपातकालीन पंजीकरण, बिलिंग और अकाउंट्स, प्रयोगशाला, रेडियोलोजी/इमेजिंग, पिक्चर आर्काइविंग और संचार प्रणाली, आईपीडी (दाखिला, डिस्चार्ज और ट्रांसफर), ओटी मैनेजमेंट, फार्मेसी मैनेजमेंट इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रिकार्ड (ईएमआर), जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, भंडार और माल सूची, कार्मिक प्रबंधन संबंधी साफ्टवेयर शामिल

The total expenditure for the budget estimates 2016-17 are ₹3450.81 crore against ₹3077.31 crore provided in revised estimates 2015-16 and actuals of ₹3041.17 crore in 2014-15. The budget estimates for revenue expenditure in 2016-17 are ₹3038.34 crore against ₹2885.38 crore provided in revised estimates 2015-16 and actuals of ₹2826.97 crore in 2014-15. The Capital Expenditure is projected at ₹412.47 crore in BE 2016-17 (including ₹76 crore for Smart Projects) against ₹191.93 crore in RE 2015-16 (including ₹11 crore for Smart Projects) and actuals of ₹214.20 crore in 2014-15.

After selection in Stage-I of the Smart City Mission, NDMC has submitted the Smart City Proposal to the Ministry of Urban Development, Government of India (**MoUD**) on 15th December, 2015 for Stage-II of the Smart City Mission. If NDMC gets selected under the Smart City Mission, it is expected to receive an amount of upto ₹194 crore from the MoUD in the form of tied grant as first installment, which shall be matched by an equal contribution by the NDMC.

2 Smart Medical Services

NDMC is continually improving the conditions that enable its citizens to enjoy the best health and well-being through its two hospitals, two poly-clinics and 38 dispensaries. I am proposing to modernize medical services related infrastructure in the year 2016-17 as follows:

(i) Hospital Management Information System in all healthcare institutions

It is proposed to improve the efficiency and effectiveness of the health system through cloud-based integration of existing public medical facilities. This will enable access and reduce response time to avail healthcare facilities, especially to economic weaker section of the society, through a centralized portal. NDMC has initiated to move to the NIC cloud based Hospital Management Information System (**HMIS**), which is the first in the country in a government setup. The software comprise of various modules making the health care delivery more efficient, like Patient Registration, Clinics, Emergency Registration, Billing & Accounts, Laboratory, Radiology/ Imaging, Picture Archiving and Communication System, IPD (Admission, Discharge & Transfer), OT Management, Pharmacy Management, Electronic Medical Records (EMR), Birth & Death Registration, Stores and Inventory, Personnel Management.

हैं। इससे रोगियों की बेहतर देखभाल करने और अच्छे परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रथम चरण में, एचएमआईएस के कुछ माड्यूल चरक पालिका अस्पताल, पालिका प्रसूति अस्पताल, और पालिका हेल्थ काम्प्लेक्स में नवंबर, 2015 से काम कर रहे हैं। मैं, 2016-17 में न.दि.न.परिषद् के सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अपेक्षित माड्यूलों का विस्तार करने और उन्हें प्रचालित करने का प्रस्ताव करता हूँ । सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान एक ब्रॉडबैंड संचार नेटवर्क के जरिए जोड़े जाएंगे।

(ii) वर्तमान चरक पालिका अस्पताल में अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण

चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती हुई माँग को पूरा करने एवं उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित के गठन हेतु लगभग ₹5 करोड़ की लागत पर चरक पालिका अस्पताल में अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण का प्रस्ताव है:

क- विशिष्ट जाँच हेतु माइक्रोबायोलाजी के समाविष्ट कार्यक्षेत्र के साथ अत्याधुनिक पैथालॉजी-सह बायोकैमेस्ट्री लैब।

ख- भली प्रकार सुसज्जित फीजियोथैरेपी सेन्टर।

ग- आपरेशन पश्चात् स्वास्थ्य लाभ इकाई (पोस्ट आपरेशन रिकवरी यूनिट) तथा शल्य-चिकित्सा आईसीयू; तथा

घ- सभी नवीनतम उपकरणों के साथ दो अत्याधुनिक आपरेशन थियेटर

(iii) 250 बिस्तर वाले सुपर स्पेशिलिटी चरक पालिका अस्पताल का निर्माण फेस-II

चरक पालिका अस्पताल वर्ष 1962 में 15 बिस्तर वाले परिवार कल्याण के रूप में आरम्भ हुआ था। समय के साथ चरक पालिका अस्पताल की सेवाओं में बहुविध वृद्धि हुई है। वर्तमान में, इसमें समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु 150 बिस्तरों की क्षमता है। बेहतर सुविधा तथा बेहतर परिणाम के साथ, धीरे-2 न केवल रोगियों की संख्या में अपितु विविधता तथा जटिलता में भी वृद्धि होगी। इन्डोक्रीनोलॉजी, कार्डियोलॉजी,गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी, रिमेटोलॉजी, यूरोलॉजी, नियोरोलॉजी, साइकैट्री तथा नेफ्रोलॉजी कुछ मुख्य सुपर स्पैशिलिटी शाखाएं हैं जिनमें हम रोगियों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं। तद्नुसार 3 वर्षों के भीतर 250 करोड़ के निवेश के साथ एक उन्नत 250 बिस्तर वाले सुपरस्पैशिलिटी अस्पताल, चरक पालिका अस्पताल-II स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

(iv) चरक पालिका अस्पताल में आपातकालीन आपरेशन थियेटर

चरक पालिका अस्पताल में आपातकालीन सेवा सुविधाएं मुख्यत: चिकित्सा सेवाओं में की जाती है यद्यपि शल्य चिकित्सा की आपात स्थिति में सामान्यत: अन्य विशिष्ट अस्पतालों में भेजा जाता है। इसे तथा चिकित्सा क्षेत्र की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए, चरक पालिका

This in-turn will lead to better patient care and improved outcome as well. In the first phase, few modules of the HMIS have been initiated working in Charak Palika Hospital, Palika Maternity Hospital, and Palika Health Complex since November 2015. I am proposing to extend and operationalize requisite modules in all NDMC healthcare institutions in 2016-17. All healthcare institutions would be connected through a broad band communication network.

(ii) Construction of Additional Block in existing Charak Palika Hospital

In order to meet the ever increasing demand and to achieve the highest standards in the Medical sector, it is proposed to construct Additional Block at Charak Palika Hospital at the cost of about ₹5 crore for setting up of:

a. state-of-art Pathology-cum-Biochemistry Lab with scope to incorporate Microbiology for specialized investigations;
b. a well equipped physiotherapy centre;
c. a post operation recovery unit and a surgical ICU; and
d. two state-of-art Operation theatres with all the latest equipments.

(iii) Construction of 250-bedded super-specialty Charak Palika Hospital Phase - II

Charak Palika Hospital started as a 15-bedded Family Welfare Centre in the year 1962. With time, the services at Charak Palika Hospital increased manifolds. At present, it has a capacity of 150 beds to cater the needs of the society. With better facility and better outcome, the patient burden is gradually going to increase, not only in number but also in variety and complexity. Endocrinology, Cardiology, Gastroenterology, Rheumatology, Urology, Neurology, Psychiatry and Nephrology are some of the major super-specialty branches in which we are seeing a rise in number of patients. Accordingly, it is proposed to establish an advanced 250-bedded super-specialty hospital, Charak Palika Hospital-II, with an investment of ₹250 crore within 3 years.

(iv) Emergency Operation Theatre at Charak Palika Hospital

Emergency service facility at Charak Palika Hospital mainly deals with medical emergencies, whereas surgical emergencies are generally referred to other specialized hospitals. In view of this and the progress in the medical sector,

अस्पताल में उपलब्ध आपातकालीन सेवाओं में शल्य चिकित्सा के लिए क्षमता के निर्माण सहित तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है। तद्नुसार एक आपातकालीन आपरेशन थियेटर की स्थापना करते हुए चरक पालिका अस्पताल में आपातकालीन सुविधा का उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

(v) चरक पालिका अस्पताल/पालिका हैल्थ कॉम्पलैक्स, धर्म मार्ग पर सीटी तथा एमआरआई सुविधाएं

सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मांग और अपेक्षाओं के बढ़ने के फलस्वरूप 'तीव्र परिणाम जांच' इनमें सुधार हेतु एक मूल आवश्यकता बन गई है। यद्यपि आधुनिक युग में क्लीनिकल प्रैक्टिस में सीटी स्कैन तथा एमआरआई मूलभूत निदान जांचे बन गई है। बहुत-सी अति-महत्वपूर्ण आपातकालीन स्थितियाँ है जिनमें उपचार मूलत: सीटी स्कैन के परिणामों मुख्य रूप से मार्गदर्शन द्वारा दिया जाता है -जैसे कि स्ट्रोक के मामले में। ऐसे अधिकांश मामलों में, आपात स्थिति से सफल परिणाम हेतु समय बहुत कम होता है। अत: भारत सरकार के मुख्य अस्पतालों के अनुरूप चरक पालिका अस्पताल/पालिका हैल्थ कॉम्पलैक्स, धर्म मार्ग में पीपीपी मॉडल के अंतर्गत सीटी तथा एमआरआई केन्द्र बनाए जाने प्रस्तावित है।

(vi) चरक पालिका अस्पताल में विडियो कान्फ्रेंसिग की सुविधा

चरक पालिका अस्पताल तथा पालिका प्रसूति अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञों की सही समय पर आनलाइन सेवाओं के उपयोग की सुविधा देने हेतु विडियों-कान्फ्रेसिंग की सुविधा लगाना प्रस्तावित किया जाता है।

(vii) पालिका प्रसूति अस्पताल का सशक्तिकरण

65 बिस्तरों वाले पालिका प्रसूति अस्पताल को आधुनिक निदान प्रयोगशाला देते हुए सशक्त किया जाएगा । बढ़ती हुई मांग के साथ तालमेल बनाने के लिए शिफ्टों को दुगुना करते हुए आपरेशन थियेटर की सुविधा को बढ़ाने हेतु भी कार्रवाई की जाएगी।

(viii) सफाई-सेवकों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच

न.दि.न.परिषद् ने इंडिया कैंसर सोसाइटी के सहयोग से कैंसर का पता लगाने हेतु 40 वर्ष से अधिक की आयु के 1274 सफाई -सेवकों के स्वास्थ्य की जांच हेतु अगस्त-सितम्बर 2015 के मासों में स्वास्थ्य जांच आयोजित की। 80 सफाई सेवकों में पूर्व-कैंसर घाव पाए गए तथा 31 प्रतिशत हाइपरटेंशन से पीड़ित थे। इसलिए, यह प्रस्तावित किया जाता हैं कि (40 वर्ष एवं अधिक आयु के) मस्टर रोल कर्मचारियों सहित सभी सफाई सेवकों की जांच नियमित रूप से वार्षिक आधार पर की जाएगी। विशेषत: वर्ष 2016-17 में हृदय-संबंधी

the emergency facility available at Charak Palika Hospital needs a technical upgrade, including capacity building for surgical interventions. Accordingly, it is proposed to upgrade the emergency facility at Charak Palika Hospital by establishing an emergency Operation Theatre.

(v) CT and MRI facility at Charak Palika Hospital / Palika Health Complex, Dharam Marg

In the wake of increasing demand and expectations from vast section of people for improved health care services, high-end investigations at public sector health care delivery units are becoming a genuine necessity. Moreover, investigations like CT scan and MRI have become basic diagnostic tests in modern day clinical practice. There are many acute emergency conditions where the treatment is principally guided by CT scan findings, like in the case of Stroke. In most of these cases, event-to-intervention time is very narrow for a successful outcome. Therefore, it is proposed to have a CT and MRI centre under PPP model at Charak Palika Hospital / Palika Health Complex, Dharam Marg as followed by major Government of India hospitals.

(vi) Video conferencing facility at NDMC Hospitals

It is proposed to set-up video-conferencing facility at Charak Palika Hospital and Palika Maternity Hospital to facilitate utilization of real-time online services of medical experts.

(vii) Strengthening of Palika Maternity Hospital

65 bedded Palika Maternity Hospital will be strengthened by adding a modern diagnostic laboratory. Action will also be taken to extend the Operation Theater facility by doubling the shifts to cope with the increasing demand.

(viii) Annual health check-up of Safai-sevaks

In the months of August-September, 2015, NDMC organized health check-up of 1274 safai-sevaks, of more than 40 years age, for cancer detection in collaboration with the Indian Cancer Society. 80 safai-sevaks were found to have pre-cancerous lesion, and 31% were suffering from hypertension. Therefore, it is proposed that check-up of all safai-sevaks (40 years and older), including those on muster-rolls, will be done on an annual basis regularly.

धमनी रोगों, हृदय रोगों, कैंसर, सांस की बीमारियों, मधुमेह को विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस तरह की जांचों के चिकित्सीय रिकार्डो को भविष्य के संदर्भों के लिए इलैक्ट्रोनिक रूप से रखा जाएगा।

(ix) डेंटल आपरेशन थियेटर

न.दि.न.परिषद् में बहुत अधिक संख्या में ओरल सर्जरी के रोगियों का आगमन होता है। वर्तमान में न.दि.न.परिषद् चिकित्सा स्टॉफ के साथ ऐसे रोगियों को इलाज को प्राप्त करने हेतु चरक पालिका अस्पताल जाना पड़ता है जोकि पद्धति की दक्षता को कम करता हैं। न. दि.न.परिषद् के पास धर्म मार्ग पर मानवीय संसाधनों के साथ-साथ कुशलता भी हैं, किन्तु डेंटल आपरेशन सुविधा के मामले में आधारभूत-ढांचे की कमी है। तद्नुसार धर्म-मार्ग पर विद्यमान डेंटल ओपीडी में डेंटल ऑपरेशन थियेटर स्थापित करना प्रस्तावित किया जाता है।

(x) बीडीएस स्नातकों हेतु क्लीनिकल शिक्षुता

मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीडीएस स्नातकों को प्रायोगिक प्रशिक्षण देते हुए वेतन भोगी शिक्षुता की पेशकश दे रहा है। न.दि.न.परिषद् ओर्थोडोटिक्स प्रोस्थोडोंटिक्स तथा ओरल सर्जरी में बड़ी संख्या में डेंटल रोगियों को देख रही हैं। हम छः बीडीएस स्नातकों अर्थात् इन तीन क्लीनिकल शाखाओं में प्रत्येक में दो, को मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अनुसार चार मास की अवधि हेतु वेतनभोगी क्लीनिकल शिक्षुता की पेशकश भी दे सकते हैं। यह न केवल ऐसे स्नातकों को प्रकाश में लाएगा अपितु सामान्य नागरिकों को बेहतर डेंटल सर्विसिज उपलब्ध करवाने में भी सहायता करेगा तथा इससे राजस्व अर्जन की संभावना भी है।

(xi) आयुष पोलीक्लीनिक

स्वास्थ्य देखभाल सेवा का एकमात्र प्रयोजन रोगियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे यह देखभाल किस पद्धति से प्रदान की जाए। अनेक बीमारियां ऐसी हैं, जिनका उपचार आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी आदि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से बेहतर ढंग से किया जा सकता है। कई बार रोगी के उपचार में उसके विश्वास की अहम भूमिका होती है। इसलिए सरोजिनी नगर में पंचकर्म संस्थान और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान सहित एक अत्याधुनिक आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी) पोलीक्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से वित्तीय सहायता मांगी जाएगी। प्रारम्भ में, प्रस्तावित क्लीनिक धर्म मार्ग पर स्थापित किया जाएगा तथा साथ ही साथ सरोजनी नगर में स्थायी व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा।

Specifically, coronary artery disease, heart diseases, cancer, respiratory diseases and diabetes will be given special attention during the year 2016-17. Medical records of such check-ups will be maintained electronically for future references.

(ix) Dental Operation Theatre

NDMC receives a large number of patients requiring oral surgery. At present, such patients alongwith the NDMC medical staff have to go to Charak Palika Hospital to get the procedure done, which decreases the efficiency of the system. NDMC has the skill as well as the human resources, but lacks infrastructure in terms of dental operation facility at Dharam Marg. Accordingly, it is proposed to set-up a Dental Operation Theatre at the existing Dental OPD at Dharam Marg.

(x) Clinical Apprenticeship to BDS graduates

Maulana Azad Institute of Dental Sciences is offering paid Clinical Apprenticeship to BDS graduates for giving them hands-on training. NDMC is handling a sizeable number of dental patients in Orthodontics, Prosthodontics and Oral Surgery. We may also offer paid Clinical Apprenticeship to six BDS graduates i.e. two each in these three clinical branches for a period of four months in line with Maulana Azad Institute of Dental Sciences. This will not only give exposure to such graduates but also help in providing better dental services to the public, and is expected to generate revenue.

(xi) AYUSH Polyclinic

The sole purpose of health care delivery unit is betterment of patient. It does not matter if he gets it from one system of medicine or the other. There are many diseases which respond better to alternative system of medicines like Ayurveda, Naturopathy, Homeopathy, Unani etc. On some occasions, it is only the faith of the patient, which is actually working on his ailment. Therefore, it is proposed to establish a state-of-art AYUSH (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Homeopathy) polyclinic, including Panchkarma Sansthaan and Naturopathy at Sarojini Nagar for which financial assistance would be sought under National AYUSH Mission from the Ministry of AYUSH, Government of India. Initially, the proposed clinic would be housed at Dharam Marg and simultaneously permanent set-up would be developed at Sarojini Nagar.

(xii) वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली

नागरिकों को वायु गुणवत्ता जानकारी वास्तविक समय पर संप्रेषित करने के लिए न.दि.न. परिषद् क्षेत्र में तीन स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 20 X 10 फुट आकार की मल्टी-मीडिया एलईडी स्क्रीनों का सहारा लिया जाएगा, जिनका इस्तेमाल विज्ञापन द्वारा राजस्व अर्जित करने के लिए भी किया जाएगा।

वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पूंजी व्यय के रूप में ₹15.25 करोड़ और राजस्व व्यय के रूप में ₹125.67 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि 2015-16 के संशोधित अनुमान में पूंजी राजस्व के लिए ₹4.69 करोड़ और राजस्व व्यय के लिए ₹112.00 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा सेवाओं हेतु पूंजी राजस्व के लिए ₹10.00 करोड़ स्मार्ट सिटी निधि से रखे जाएंगे।

3. स्मार्ट शिक्षा

डिजिटल युग में आगे बढ़ने और नागरिकों को इस बदलाव के लिए तैयार करने के वास्ते न.दि.न.परिषद् को शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता है। वर्ष 2016-17 में, न.दि.न.परिषद् के सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक स्मार्ट क्लास-रूमों के जरिए ई-लर्निंग सोल्यूशंस प्रदान करने का प्रस्ताव है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और व्यावसायिक दृष्टि से विकसित शिक्षण सामग्री को शामिल करते हुए स्मार्ट क्लास रूम परंपरागत क्लास रूमों को भावी प्रौद्योगिकी सक्षम स्मार्ट शिक्षण कक्षाओं में तब्दील करेंगे। विषय पाठ्यक्रम डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शिक्षण में सुविधा होगी। वर्चुअल प्रयोगशालाएं और डिजिटल लायब्रेरी स्मार्ट क्लासरूम परियोजना का हिस्सा होंगी।

इन क्लास रूमों में हाई-एंड कम्प्यूटर, इंटर-ऐक्टिव व्हाइट बोर्ड, शार्ट-थ्रो प्रोजेक्टर और अन्य हार्डवेयर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्मार्ट कक्षाओं को एक स्कूल आधारित सर्वर के साथ जोड़ा जाएगा। इससे, स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आएगी और ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के जरिए ज्ञान धारण क्षमता में सुधार होगा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया को खेल जैसा बनाने में मदद मिलेगी।

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के साथ वैज्ञानिक ढंग से नियमित आधार पर शिक्षकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे समाज के उपेक्षित वर्गों के बच्चों को परामर्श प्रदान करें।

सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य निरीक्षण हेतु स्वास्थ्य रिकार्डों के संग्रह का भी प्रस्ताव है।

(xii) Air Quality Monitoring System

It is proposed to set-up Air Quality Monitoring System at three places in the NDMC area to disseminate real-time air quality information to the citizens through 20 X 10 feet multi-media LED screens, which will be used for advertisement purpose for revenue generation.

A provision of ₹15.25 crore for capital expenditure and ₹125.67 crore for revenue expenditure for Health sector has been kept in BE 2016-17, as against ₹4.69 crore for capital expenditure and ₹112.00 crore for revenue expenditure in RE 2015-16. In addition, ₹10.00 crore for capital expenditure will be kept from Smart City funds for medical services.

3 Smart Education

NDMC needs to improve education to move ahead in the digital era, and citizens need to adapt to change. In the year 2016-17, Smart Classrooms are proposed to provide e-learning solutions in all NDMC schools from classes VI to XII. Smart classrooms would transform traditional classrooms into futuristic technology enabled smart learn classes by amalgamating state-of-art technology, infrastructure and professionally developed learning content. The subject curriculum would be made available digitally to facilitate teaching. Virtual-labs and digital library will be a part of the smart classroom project.

Such classrooms will be provided with high-end computers, interactive white boards, short-throw projector and other hardware. Such smart classes will be connected through a school-based server. This will reduce student dropouts and improve knowledge retention through leveraging e-Learning that leads to gamification of education.

The performance of teachers will be evaluated on a regular basis in a scientific manner with capacity building programmes. Senior citizens will be requested to mentor students from under-privileged sections of the society.

It is also proposed to maintain the repository of health records of all the students for monitoring their health.

मैं बास्केट बाल, बैडमिन्टन, वॉलीबाल, टैनिस तथा योगा सहित ₹4.46 करोड़ की लागत के साथ न.दि.न.परिषद् के 10 विद्यालयों में खेल की सुविधाओं का उन्नयन प्रस्तावित करता हूँ। न.दि. न.परिषद् के विद्यार्थियों के लिए हॉकी तथा फुटबाल की कोचिंग भी आयोजित की जायेगी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत नेशनल स्किल डिवलपमेंट काउंसिल (एनएसडीसी) के सहयोग से विद्यार्थियों को भावी कौशलों जैसे 3 डी प्रिन्टिंग, कम्प्यूटर ग्राफिक्स तथा एनीमेशन प्रदान करने हेतु न.दि.न.परिषद् विद्यालयों में तीन स्किल ट्रेनिंग सेन्टर का गठन किया जायेगा।

हम वर्ष 2016-17 के दौरान रोजगारोन्मुख कुशलताओं हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाये जा रहे वर्ल्ड क्लास स्किल सेन्टर, विवेक विहार की तर्ज पर महिला तकनीकी संस्थान (डब्ल्यू,टी,आई) के संरचनात्मक उन्नयन का प्रस्ताव रखते हैं।

हमने शिक्षा सेवाओं हेतु बजट अनुमान 2016-17 में ₹187.71 करोड़ का प्रावधान रखा है, जिसमें, ₹9.92 करोड़ पूंजीगत व्यय हेतु है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी निधि से स्मार्ट एजुकेशन हेतु ₹9.00 करोड़ रखे जाएंगे।

4. स्मार्ट जलापूर्ति

हमारे पास लगभग 470 कि.मी. पेयजल नेटवर्क, जिसमें से लगभग 30 प्रतिशत के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। न.दि.न.परिषद् का लक्ष्य 24 घण्टें गुणवत्ता व भरोसेमंद जलापूर्ति उपलब्ध कराना है। जिसके लिए जलापूर्ति संरचनाओं के पुनर्वास, मरम्मत, सफाई तथा प्रतिस्थापन के लिए पूँजीगत व्यय की आवश्यकता होगी।

इसलिए, मैं जलापूर्ति संरचना सशक्तिकरण के लिए, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की अटल मिशन रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफार्मेशन (एएमआरयूटी) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 2 वर्षीय कार्यक्रम का प्रस्ताव रखता हूँ। ₹128 करोड़ की दो वर्षीय योजना में निम्न परिकल्पित है:

i ₹67 करोड़ की लागत पर न.दि.न. परिषद् के वर्तमान जल वितरण प्रणाली का पुनर्वास तथा उन्नयन।

ii ₹30 करोड़ की लागत पर एएमआर मीटरों को उपलब्ध करना एवं लगाना।

iii ₹11 करोड़ की लागत पर पम्पहाउसों का संवर्धन/पुनर्वास।

iv ₹20 करोड़ की लागत पर ऑटोमेशन/उपकरणों के प्रयोग सहित एससीएडीए को लागू करना।

I am proposing to upgrade sports facilities in 10 schools of NDMC at a cost of ₹4.46 crore, including Basket Ball, Badminton, Volley Ball, Tennis and Yoga. The coaching of NDMC students in hockey and football will be organized regularly.

Three Skill Training Centres will be set-up in NDMC schools for imparting future skills like 3-D printing, computer graphics and animation to the students in collaboration with National Skill Development Council (NSDC) under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna.

We propose an infrastructure upgrade of Women Technical Institute (WTI), on the lines of world class Skill Centre, Vivek Vihar, run by Delhi Government, for job oriented skills during the year 2016-17.

We have kept a provision of ₹187.71 crore in BE 2016-17 for Education services , out of which ₹9.92 crore are for capital expenditure. In addition, ₹9.00 crore would be kept for Smart Education from Smart City funds.

4 Smart Water Supply

We have about 470 km of potable water network, out of which, about 30% requires replacement. The mission of NDMC is to provide 24x7 quality and reliable water supply to its residents. For which, capital expenditure would be required to rehabilitate, repair, refurbish & replace water supply infrastructures.

Therefore, I am proposing a two years program starting from 2016-17 under Atal Mission Rejuvenation of Urban Transformation (**AMRUT**) scheme of the Ministry of Urban Development, Government of India to strengthen water supply infrastructure. The two year plan of ₹128 crore envisages:

i. undertaking rehabilitation and an upgrade of existing Water Distribution System of NDMC at a cost of ₹67 crore;
ii. providing & fixing AMR meters at a cost of ₹30 crore;
iii. augmenting / rehabilitating pump houses at a cost of ₹11 crore; and
iv. automating and implementing SCADA system at a cost of ₹20 crore.

परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा बांटा जायेगा। शेष 50 प्रतिशत न.दि.न.परिषद् के आन्तरिक संसाधनों से प्राप्त किया जायेगा। इस संबंध में प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान में, न.दि.न.परिषद् दिल्ली जलबोर्ड से लगभग 125 एमएलडी पेय जल प्राप्त करती है। गैर राजस्व जल हानि लगभग 38.7 प्रतिशत है। इस योजना के लागू होने के साथ यह आशा की जाती है कि गैर राजस्व जल हानि 15 प्रतिशत तक तथा इससे कम हो जायेगी।

मैं वर्ष 2016-17 में वाटर ऑडिट प्रारंभ कराना प्रस्तावित करता हूँ जिससे नुकसान का पता लग सके तथा इसे कम करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की जा सके। मैं वर्ष 2016-17 में सभी वाटर बूस्टिंग पम्पों का ऊर्जा ऑडिट कराना प्रस्तावित करता हूँ। ऊर्जा ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर पम्पों को ऊर्जा दक्ष प्रणाली के साथ प्रतिस्थापित तथा संशोधित किया जायेगा। बूस्टिंग स्टेशनों के साथ-साथ सभी जलाशयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे भली प्रकार फिजिकल इलैक्ट्रोनिक गैजड से सुरक्षित किए जाएगें।

गुणवत्ता पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चत करने के लिए, वर्ष 2016-17 में पीपीपी मोड पर सभी 24 झुग्गी-झोपड़ी समूहों में पानी के एटीएम संस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। बेहत्तर गुणवत्ता जल हेतु उपभोक्ताओं से नाममात्र जल प्रभारों को वसूल किया जायेगा।

जलापूर्ति के लिए संशोधित अनुमान 2015-16 में राजस्व व्यय हेतु ₹122.09 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय हेतु ₹7.53 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2016-17 में पूंजीगत व्यय हेतु ₹11.38 करोड़ तथा राजस्व व्यय हेतु ₹121.69 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट सिटी के लिए प्रावधान से ₹9.00 करोड़ चिन्हित किए जाएगे।

5. सीवरेज

न.दि.न.परिषद् का अपने क्षेत्र में लगभग 300 कि.मी. का सीवरेज नेटवर्क है। निवारक रखरखाव के प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए दीर्घ अवधि आधार पर जेटिंग सुविधा के साथ दो सक्शन-सह-रिसाइकिलर मशीनों को किराए पर लेने का प्रस्ताव है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एएमआरयूटी योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित को आरंभ करना प्रस्तावित है:

i ₹19.66 करोड़ की लागत पर के.जी. मार्ग, शाहजहां रोड पर 84'' व्यास ब्रिक बैरल सीवर लाइन की गाद हटाना तथा बहालीकरण

ii ₹12.0 करोड़ की लागत पर अशोका रोड में 1100-1200 व्यास आरसीसी पाईप की गाद हटाना तथा बहालीकरण; तथा

50% of total project cost would be shared by the Government of India and Government of NCT of Delhi. Balance 50% shall be met through internal resources of NDMC. The proposal in this regard is submitted to the Government.

Presently, NDMC is getting about 125MLD treated water from DJB. The non-revenue water losses are about 38.7%. With the implementation of the Plan, it is expected that non-revenue water losses would reduce to 15% and less.

I am proposing to undertake Water Audit in the year 2016-17 so that the losses can be detected and appropriate action can be taken to reduce the same. I am proposing to undertake Energy Audit of all the Water Boosting pumps in the year 2016-17. Based on the report of the Energy Audit, the pumps will be replaced or modified with energy efficient system. All water storage reservoirs as well as boosting stations shall be properly secured with physical electronic gadgets to ensure their security.

To ensure quality drinking water supply, it is proposed to install Water ATMs in all 24 J.J. Clusters on PPP mode in the year 2016-17. Nominal water charges shall be levied to the consumer for best water quality to the residents.

A provision of ₹11.38 crore for capital expenditure and ₹121.69 crore for revenue expenditure for Water Supply has been kept in BE 2016-17, as against ₹7.53 crore for capital expenditure and ₹122.09 crore for revenue expenditure in RE 2015-16. In addition, ₹9.00 crore would be earmarked from the provision for Smart City.

5 Sewerage

NDMC has about 300 km of sewerage network in its area. For effectiveness of preventive maintenance efforts, it is proposed to hire two suction-cum-recycler machines with jetting facility on long term basis.

Under AMRUT scheme of the Ministry of Urban Development, Government of India, it is proposed to undertake:

i. Desilting and rehabilitation of 84” dia brick barrel Sewer Line on K.G. Marg - Shahjahan Road at the cost of ₹19.66 crore;
ii. Desilting and rehabilitation of 1100-1200 dia RCC pipe at Ashoka Road at the cost of ₹12.0 crore; and

iii न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में 5.0 एमएलडी की कुल क्षमता के 11 सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों (एसटीपी) का संस्थापन। एसटीपी की यह योजना वर्ष 2016-17 में चालू होने की संभावना है। इन एसटीपी से उपचारित पानी का उद्यान प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जायेगा।

कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत भारत सरकार तथा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत न.दि.न.परिषद् के आंतरिक संसाधनों से आएंगे। इस संबंध में प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

संशोधित अनुमान 2015-16 में राजस्व व्यय के लिए ₹56.10 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय के लिए ₹5.11 करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2016-17 में सीवरेज हेतु राजस्व व्यय के लिए ₹58.26 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय के लिए ₹9.62 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। स्मार्ट सिटी निधि से इस क्षेत्र हेतु ₹9.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान होगा।

6. स्वच्छ न.दि.न.परिषद्

स्वच्छ न.दि.न.परिषद्, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम है, जिसके लक्ष्यों में नगर के ठोस कचरे के प्रचालन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करना, स्वस्थ स्वच्छता पद्धतियों के बारे में व्यवहारगत परिवर्तन लाना और इस कार्यक्रम को जन-स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हुए स्वच्छता के प्रति जागरुकता पैदा करना शामिल है।

मैं, वर्ष 2016-17 में सरकारी-निजी-भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत विकलांगों के अनुकूल करीब 100 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय इकाईयों के निर्माण का प्रस्ताव करता हूँ। प्रस्तावित सार्वजनिक शौचालय स्मार्ट जन-सुविधाएं केन्द्र होंगे, जिनमें पेयजल डिस्पेंसर, बैंक एटीएम, रक्त संग्रह केन्द्र जैसी सुविधाएं स्थान की उपलब्धता के अनुसार और प्रत्येक स्थल की जरूरत के मुताबिक प्रदान की जायेगी। इन शौचालयों में छत पर रखे सोलर फोटोवोल्टैइक पैनलों द्वारा विद्युतीकृत एलईडीज़ प्रयुक्त किए जाएंगे। एलईडीज़ के जरिये विज्ञापन पैनल बैकलिट और प्रकाशित किए जाएंगे।

शहर का ठोस कचरा घर-घर जाकर एकत्र करने की जो सुविधा 2014 में शुरू की गई थी, उसका विस्तार 2016-17 में उपभोक्ता-प्रभार के आधार पर डिप्लोमैटिक मिशनों सहित वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों में किया जायेगा। 2016-17 में आर्गेनिक कचरे से एक टन क्षमता का बायो-मीथेनाइजेशन प्लांट पिलंजी गाँव में लगाया जायेगा। सफाई सेवकों को ट्राईसाइकिल भी उपलब्ध कराई जाएगी।

iii. Installation of 11 Sewage Treatment Plants (**STPs**) of total capacity of 5.0 MLD in NDMC area. This scheme of STPs on PPP model is expected to be commissioned in the year 2016-17. The treated water from these STPs would be used for horticulture purposes.

50% of the total project cost will be provided by the Government of India and Government of NCT of Delhi, and balance 50% will come from internal resources of NDMC. The proposal in this regard is submitted to the Government.

A provision of ₹9.62 crore for capital expenditure and ₹58.26 crore for revenue expenditure for Sewerage has been kept in BE 2016-17, as against ₹5.11 crore for capital expenditure and ₹56.10 crore for revenue expenditure in RE 2015-16. Additional provision of ₹9.00 crore would be made for this sector from the Smart City funds.

6 Swachh NDMC

Swachh NDMC is an initiative under the Swachh Bharat Mission to bring modern and scientific techniques for handling municipal solid waste, to effect behavioural change regarding healthy sanitation practices, and generate awareness about sanitation and its linkage with public health.

I am proposing to construct about 100 modern disabled friendly Public Toilet Units under PPP model in 2016-17. Proposed public toilets would be Smart Public Amenities Centres having drinking water dispenser, bank ATM, blood collection centre as per the space availability and the need at each location. LEDs would be used in these toilets powered by solar photovoltaic panels installed on roof-tops. Advertisement panels would be backlit and lighted by LEDs.

Door-to-door municipal solid waste collection facility, which was introduced in the year 2014, will be extended to commercial and institutional areas, including diplomatic missions, on user-charge basis in the year 2016-17. One tonne capacity bio-methanisation plant at Pillanji village will be set-up in 2016-17 from organic wastes. Safai Sevaks would also be provided tri-cycles.

न.दि.न.परिषद् क्षेत्र को कूड़ा-करकट मुक्त बनाने के लिए, 2016-17 में 1 करोड़ रुपये की लागत से सभी प्रमुख सड़कों और मार्किटों में स्टेनलेस स्टील के कूड़ेदान और सभी प्रमुख उद्यानों/गार्डनों में हल्के इस्पात पाउडर कोटिड कूड़ेदान प्रदान करने का प्रस्ताव है। सभी प्रमुख एवेन्यू सड़कों पर रात के समय यंत्रीकृत स्वीपिंग (झाड़ू लगाने) की व्यवस्था की जायेगी।

वर्ष 2016-17 में भवनों के निर्माण और ढांचे गिराने से सृजित होने वाले मलबे के संग्रह और निपटान के लिए पीपीपी मॉडल की एक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जायेगा और कार्यान्वित किया जायेगा।

नागरिकों में समुचित व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए प्रिन्ट और इलैक्ट्रोनिक दोनों ही रूपों में आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) मॉड्यूल विकसित किए जायेंगे।

7. हरित एवं खुशहाल न.दि.न.परिषद्

न.दि.न.परिषद् ने दिल्ली में 21 प्रतिशत के औसत हरित क्षेत्र के विपरीत 48 प्रतिशत हरित क्षेत्र को विकसित किया है। उद्यान विभाग 110 एवेन्यू, 8 प्रमुख उद्यानों, 122 कॉलोनी पार्कों तथा 981 के.लो.नि.वि. कालोनी पार्कों का रखरखाव करती है। वर्ष 2015-16 में, उद्यान विभाग ने 1 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। हरित क्षेत्र के विकास तथा रखरखाव में न.दि.न.परिषद् के प्रयासों की व्यापक रूप से सराहना की जाती है। मैं अगले दो वर्षों में न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में कुल 50 प्रतिशत हरित क्षेत्र विकसित करना प्रस्तावित करता हूँ।

वर्ष 2015-16 में शांतिपथ पर रोज गार्डन भाग-1 विकसित किया गया है। मैं वर्ष 2016-17 में चार उद्यानों अर्थात् लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन, रोज गार्डन भाग-II व नेहरू पार्क को ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था तथा जल निकायों सहित विश्व स्तर के उद्यानों में विकसित करना प्रस्तावित करता हूँ। न.दि.न.परिषद् क्षेत्र के सभी प्रमुख उद्यानों में सीटिंग बैंचों की वृद्धि करना प्रस्तावित किया जाता है। वर्ष 2016-17 में सभी 53 गोल चौराहों तथा एवेन्यू सड़कों को गहन वृक्षारोपण अभियान में कवर किया जाएगा।

सेन्ट्रल विस्टा, सफदरजंग मकबरे के समीप तथा चाणक्यपुरी में नमी तथा तापमान नियंत्रण प्रणाली सहित अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तीन ग्रीन हाउस नर्सरियों को विकसित करना प्रस्तावित किया जाता है। उद्यान विभाग को अपनी कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए आधुनिक औजारों तथा उपकरण उपलब्ध कराए जाएगें। सभी मालियों को बेहतर उद्यान

To make NDMC area litter free, it is proposed to provide stainless steel bins in all major roads and markets, and mild steel powder coated bins in all major parks / gardens at a cost of ₹1 crore in the year 2016-17. Mechanized sweeping will be deployed at all major avenue roads in night.

A mechanism will be finalized and implemented in the year 2016-17 for collection and disposal of construction and demolition waste on PPP mode.

IEC (Information, Education and Communication) modules, both in print and electronic form, would be developed for bringing appropriate behavioural changes in citizens.

7 Green and happy NDMC

NDMC has 48% green cover against average green cover of 21% in Delhi. The Horticulture Department maintains 110 Avenues, 8 major gardens, 122 colony parks and 981 CPWD colony parks. In the year 2015-16, Horticulture Department has planted more than 1 lakh saplings. Efforts of the NDMC in development and maintenance of the green cover are widely appreciated. I propose to increase the green cover to 50% in NDMC area in the next two years.

In the year 2015-16, Rose Garden Part-I has been developed at Shanti Path. I propose to develop four gardens in 2016-17, namely Lodi Garden, Talkatora Garden, Rose Garden Part-II, Nehru Park into world class gardens, including energy efficient lighting and water bodies. It is proposed to augment sitting benches in all the major gardens in NDMC area. Intensive plantation drive will be undertaken to cover all 53 round-abouts and Avenue roads in 2016-17.

It is proposed to develop three Green House nurseries at Central Vista, near Safdarjung Tomb, and in Chanakyapuri with state-of-art facilities that includes humidity and temperature control systems. The Horticulture Department will be provided with modern tools and equipments to improve their efficiency and effectiveness. All Malis will be given at least five days training, either in-house or through external institutions, in the best horticultural practices.

प्रैक्टिस में, या इन-हाउस अथवा बाहरी संस्थानों द्वारा कम से कम पाँच दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विद्यमान ट्यूब वैलों का पुनर्विकास

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के एएमआरयूटी योजना के अन्तर्गत, पार्कों में 50,000 लिटर की क्षमता के जलाशयों के साथ 25 बरसाती जल संचयन प्रणाली को विकसित करने का प्रस्ताव किया जाता है वर्तमान में, हमारे पास 41 परित्यक्त ट्यूबवैल है जिनकी जल तालिका मरम्मत से परे हैं। इसलिए इनका उपयोग बरसाती जल संचयन प्रणाली के लिए करना प्रस्तावित किया जाता है। लगभग 30 ट्यूबवैलों का वर्तमान में उद्यान प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा रहा है किन्तु लाभ कम है, इसलिए इन ट्यूबवैलों का पुनर्विकास प्रस्तावित किया जाता है ताकि उद्यान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वर्ष 2014-15 में उद्यान कूड़े से चार खाद/पैलेट्स प्लान्ट्स स्थापित किए गए थे। यह प्रस्तावित किया जाता है कि इन प्लान्ट्स से उत्पादित पैलेट्स का विशेषकर मिट्टी को रोक कर पेड़ पौधे विहिन क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपने उपयोग हेतु न.दि.न.परिषद् द्वारा वापस खरीदा जाएगा। प्रस्तावित एसटीपी द्वारा उत्पन्न जल नियमित रूप से एवेन्यू सड़कों पर वृक्षों को धोने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

वर्ष 2016-17 में मैं शांति पथ पर रोज गार्डन, पालिका पार्किंग तथा पालिका बाजार के ऊपर, तालकटोरा गार्डन, पालिका सर्विसिज आफिसर्स इन्सटीट्यूट, नेहरू पार्क, कनाट प्लेस का सैन्ट्रल पार्क तथा इंडिया गेट पर चिल्ड्रल पार्क जहाँ मल्टी-मिडिया लाइट्स, तथा संबद्ध संरचना उपलब्ध कराई जाएगी, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए विशेष क्षेत्रों को विकसित करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। यहाँ नियमित सामाजिक, कलात्मक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित किया जाएगा।

न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में 35 विभिन्न स्थानों पर समाज के सभी वर्गों जो इण्डोर जिम तथा स्पोटर्स सेन्टरों का खर्च नहीं उठा सकते हैं, के लिए स्वास्थ्य एवं फिटनेस उपकरणों की व्यवस्था कर आउटडोर जिम की स्थापना की गई है। हम वर्ष 2016-17 के दौरान 17 नये स्थानों पर आउटडोर फिटनेस उपकरणों को स्थापित करने जा रहे हैं। इस प्रयोजन हेतु बजट अनुमान 2016-17 में 2 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

Redevelopment of existing Tube-wells:

Under AMRUT scheme of the Ministry of Urban Development, Government of India, it is proposed to develop 25 rainwater harvesting systems in parks alongwith reservoirs of 50000 litre capacity. Presently, we have 41 abandoned tube-wells for which water table is below repair limits. Therefore, it is proposed to use them as rainwater harvesting systems. About 30 tube-wells are presently being used for Horticulture purposes but the yield is low, therefore, proposed to redevelop these tube-wells, so that horticulture needs can be met.

Four Horticulture waste to compost / pellets plants were set-up in the year 2014-15. It is proposed that the pellets produced from these plants will be bought-back by NDMC for its own use especially for covering the non-planted areas to arrest dust. Water generated through proposed STPs will be used for washing the trees on avenue roads on regular basis.

In the year 2016-17, I am proposing to develop exclusive areas for cultural and social activities at Rose Gardens at Shanti Path, above Palika Parking and Palika Bazaar, Talkatora Garden, Palika Services Officers Institute, Nehru Park, Central park at Connaught Place and Children Park at India Gate, where multi-media lights and allied infrastructure would be made available. Regular social, artistic and cultural activities would be organized there.

Outdoor gyms at 35 various locations in NDMC area were installed to provide health and fitness equipments to all sections of society who cannot afford going to indoor gyms and sport centres. We are going to install outdoor fitness equipments during 2016-17 at 17 new locations. A provision of ₹2 crore has been kept in BE 2016-17 for this purpose.

बजट अनुमान 2016-17 में पार्को एवं उद्यानों हेतु ₹96.77 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से पूँजीगत व्यय के लिए 9.35 करोड़ है।

8 स्मार्ट ग्रिड एवं ऊर्जा प्रबंधन

स्मार्ट ग्रिड अधिकतम लोड प्रबंधन, नवीकरण ऊर्जा एकीकरण, उपभोक्ता सेवाओं तथा परिचालन कार्यकुशलता में सुधार का प्रबंधन करती है। स्मार्ट ग्रिड से ए टी एण्ड सी हानियों को कम कर पर्याप्त रूप से वितरण प्रणाली में सुधार, उपभोक्ता के लिए ऊर्जा बचत लाने, बिलिंग तथा संग्रह क्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी तथा इस प्रकार न.दि.न.परिषद् को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए विश्व स्तर का तथा समर्थ ऊर्जा वितरक बनाने में मदद मिलेगी।

स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन में निम्नलिखित घटक सम्मिलित है:-

क) 11 केवीए नेटवर्क का सशक्तिकरण

ख) स्काडा सुविधा देना

ग) आटोमेटिड डिमांड रिस्पान्स के साथ 100 प्रतिशत आटोमेटिड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

घ) फिल्ड फोर्स ऑटोमेशन: सबस्टेशन ऑटोमेशन

ड़) स्मार्ट मीटरों तथा ग्रिड प्रबंधन के लिए नेटवर्क

च) नेट मीटरिंग अर्थात् नवीकरण ऊर्जा एकीकरण।

छ) पावर प्रबंधन तथा मांग पूर्वानुमान, अधिकतम लोड प्रबंधन।

ज) एकीकृत वितरण प्रबंधन प्रणाली तथा बिजली न रहने की अवधि (आउटऐज) प्रबंधन प्रणाली।

झ) बिलिंग एवं ऊर्जा ऑडिट प्रणाली

ड़) शार्ट सर्किट विश्लेषण एवं रिले समन्वय

ट) ऊर्जा दक्षता प्रणाली अर्थात परिसम्पत्ति निगरानी सबस्टेशन।

ठ) न.दि.न.परिषद् भवनों के लिए ऊर्जा आडिट तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया।

स्मार्ट ग्रिड के लिए कुल परियोजना लागत ₹505 करोड़ है जिसमें से आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत पावर मंत्रालय, भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से ₹190 करोड़ का योगदान करने के लिए सहमत हो गया है। परियोजना कार्यान्वयन की अवधि 3 वर्ष होगी।

A provision of ₹96.77 crore has been kept for Parks & Gardens in BE 2016-17 out of which ₹9.35 crore are for capital expenditure.

8 Smart Grid and Energy Management

Smart Grid is to manage peak load management, renewal energy integration, improvement in operational efficiency & consumer services. The Smart Grid will help in improving the distribution systems to substantially reduce AT&C losses, bring in energy savings for consumers, improving billings and collection efficiency and thus help in making NDMC future ready, world class and sustainable as a distribution utility.

Smart Grid Implementation consists of the following components:

a) Strengthening of 11KVA network

b) SCADA enablement

c) 100% Automated Metering Infrastructure with Automated Demand Response

d) Field force automation: Sub-station automation

e) Network for smart meters and grid management

f) Net metering i.e. renewable energy integration

g) Power Management & demand forecasting, peak load management

h) Integrated distribution management system and outage management system

i) Billing and Energy Audit system

j) Short circuit analysis and relay coordination

k) Energy efficiency system i.e. asset monitoring substation

l) Energy Audit & Certification process for NDMC Building

The total project cost for the Smart Grid is ₹505 crore, out of which Ministry of Power, Government of India has in-principle agreed to contribute ₹190 crore under the IPDS scheme. The project implementation period would be 3 years.

''विद्युत हेतु स्ट्रेटीजिक बिजनैस यूनिट (एसबीयू)'' की एक पृथक स्थापना के लिए नियुक्त परामर्शदाता मै0 एसबीआई कैप्स ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की जाँच की जा रही है तथा स्वीकृत सिफारिशों को वर्ष 2016-17 में लागू किया जाएगा।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अलीगंज, जोर बाग पर 33 केवी विद्युत सबस्टेशन वर्ष 2015-16 के दौरान चालू हो गए हैं। हम एम्स, नई दिल्ली तथा अर्जुनदास कैम्प, सरोजिनी नगर में दो 33 केवी विद्युत सबस्टेशन की स्थापना प्रस्तावित करते हैं। किदवई नगर पर 33 केवी विद्युत सबस्टेशन के लिए भवन के निर्माण हेतु कार्य सौंप दिया गया है तथा वर्ष 2016-17 में कार्य पूर्ण हो जाएगा। अफ्रीका एवेन्यू क्रास रोड नं.-II, सरोजिनी नगर पर 11 केवी विद्युत सबस्टेशन की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है।

हम वर्ष 2016-17 में पिलंजी गाँव में 11 केवी विद्युत सबस्टेशन की स्थापना तथा अमेरिकन एम्बेसी स्कूल के समीप, चाणक्यपुरी में 11 केवी विद्युत सबस्टेशन का निर्माण प्रस्तावित करते हैं। एयरफोर्स स्टेशन, रेस कोर्स पर विद्युत सबस्टेशन का संवर्धन वर्ष 2016-17 में पूर्ण हो जाएगा। न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में विद्युत के कुशल वितरण के लिए विभिन्न संयंत्र एवं उपकरणों की वृद्धि करने के लिए, हम 66 केवी विद्युत सब स्टेशन के लिए पावर ट्रांसफार्मरों का क्रय तथा 990 केवीए यूनिटाइज्ड सब स्टेशनों की (क) ओल्ड एज होम, काली बाड़ी मार्ग तथा (ख) पालिका प्रसूति अस्पताल, लोधी कालोनी पर स्थापना प्रस्तावित करते हैं। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय के विद्युत आपूर्ति के सशक्तिकरण का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2015-16 में पूर्ण हो जाएगा। हम वर्ष 2016-17 के दौरान पंडारा रोड तथा गोल्फ लिंक में एलटी नेटवर्क का संवर्धन प्रस्तावित करते हैं।

बजट अनुमान 2016-17 में विद्युत वितरण हेतु ₹1276.23 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें पूंजीगत व्यय हेतु ₹116.31 करोड़ है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी निधि से ₹10.00 करोड़ का प्रावधान रखा जाएगा।

9. ऊर्जा संरक्षण और स्मार्ट लाइटिंग

प्रकाश व्यवस्था, जो एक अनिवार्य सेवा है, के क्षेत्र में नवीकरण और निरंतर सुधार से ऊर्जा की बचत के असंख्य अवसर पैदा हुए हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी बड़े न.दि.न.परिषद् भवनों का ऊर्जा लेखा परीक्षण कराया जाएगा ताकि अपेक्षित उपायों की पहचान की जा सके। सभी न.दि.न.परिषद् भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर विद्यमान लाइटों के स्थान पर स्मार्ट एलईडीज़ के इस्तेमाल के द्वारा ऊर्जा संरक्षण किया जा रहा है। न.दि.न.परिषद् भवनों में यह कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। सार्वजनिक स्थानों जैसे न.दि.न.परिषद् मार्किटों, उद्यानों आदि को वर्ष 2016-17 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करने का प्रस्ताव है।

M/s SBICAPS, Consultant, appointed for setting up of a separate "Strategic Business Unit (SBU) for electricity", has submitted its report. The report is being examined and accepted recommendations will be implemented in the year 2016-17.

I am happy to report that 33 KV ESS at Aliganj, Jor Bagh has been commissioned during 2015-16. We proposed establishment of two 33 KV ESS at AIIMS, New Delhi and Arjun Dass Camp, Sarojini Nagar. Work has been awarded for construction of building for the 33 KV ESS at Kidwai Nagar, and the work would be completed in the year 2016-17. The work of establishing 11 KV ESS at Africa Avenue Cross Road No.II, Sarojini Nagar has been completed.

We propose establishment of 11 KV ESS at Pillanji Village, and, construction of 11 KV ESS near American Embassy School, Chanakya Puri in the year 2016-17. Augmentation of ESS at Air Force Station, Race Course shall be completed in the year 2016-17. In order to augment various plant and equipments for efficient distribution of electricity in NDMC area, we propose procurement of power transformers of 66 KV ESS Vidyut Bhawan and installation of 990 KVA Unitized Sub-Stations at (a) Old Age Home, Kali Bari Marg; and (b) Palika Maternity Hospital, Lodi Colony. The work of strengthening the power supply to PMO at South Block is in progress and shall be completed in the year 2015-16. We propose augmentation of LT Network at Pandara Road and in Golf Link area during the year 2016-17.

A provision of ₹1276.23 crore has been kept for Electricity Distribution in BE 2016-17 out of which ₹116.31 crore are for capital expenditure. In addition, provision of ₹10.00 crore would be kept from the Smart City fund.

9 Energy Conservation and Smart Lighting

Innovation and continuous improvement in the field of lighting, which is an essential service, has given rise to tremendous energy saving opportunities. To conserve energy, audit of all major NDMC buildings will be undertaken to identify requisite measures. Conservation of energy is being done by replacing existing lights with Smart LEDs at all NDMC buildings and public places, and the work for NDMC buildings is expected to be completed by the end of financial year 2015-16. The public places such as NDMC markets, gardens etc. are proposed to be covered in the year 2016-17.

इससे कार्य क्षमता में सुधार आएगा और ऊर्जा की खपत में कमी आएगी। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2016-17 में ₹2 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी निधि प्रावधानों से लिए जाएंगे।

10. स्मार्ट स्ट्रीट पोल

पीपीपी मॉडल के आधार पर, यह प्रस्ताव है कि विद्यमान 18,500 बिजली के खंभों पर लगाई गई 20,500 सोडियम वेपर लाइटों/सीएफएल्स के स्थान पर स्मार्ट एलईडी लुमिनरीज़ (प्रमुख जंक्शनों और बीक्यूएस पर घटना संचालित नियंत्रक और यातायात विश्लेषकयुक्त), नगर निगरानी के लिए सीसीटीवी, सभी प्रमुख हॉटस्पॉट्स में जन-साधारण के लिए 512 केबीपीएस गति के साथ 20 मिनट तक नि:शुल्क वाईफाई सुविधा प्रदान की जाए। स्मार्ट पोलों पर जन सुरक्षा और संरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। सफल रियायत प्रदाता न.दि.न.परिषद् को अपना संचार नेटवर्क उपलब्ध कराएगा ताकि परिषद अपनी सेवाएं संचालित कर सके। इस संचार नेटवर्क का इस्तेमाल न.दि.न.परिषद् द्वारा अपने स्मार्ट सिटी कार्यक्रमों, जैसे स्मार्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा ग्रिड, जल ग्रिड, ठोस कूड़ा प्रबंधन और नागरिक सेवाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। इस परियोजना में पालिका केंद्र में एक केंद्रीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित करना भी शामिल है।

न.दि.न.परिषद् को प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं के स्थान पर रियायत प्रदाता को नि:शुल्क उपयोग की अनुमति होगी कि वह आरओडब्ल्यू, बिजली के खंभों और न.दि.न.परिषद् परिसरों का, जहां कहीं संभव हो, इस्तेमाल नेटवर्क डिवाइस लगाने के लिए कर सकेगा। रियायत की अवधि 15 वर्ष होगी। नीतिगत परिवर्तन के रूप में, रियायत प्रदाता को इस बात की अनुमति दी जाएगी कि वह अपनी लागत पर फुटपाथ और सड़कों का सुधार कर सके। वर्तमान में मरम्मत कार्य न.दि.न.परिषद् द्वारा किया जाता है।

11. सौर ऊर्जा

ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज आज समय की आवश्यकता है। इसके लिए न.दि.न.परिषद् ने भवनों की छतों पर सोलर पैनल के जरिए योजना बनाई है, जो स्थायी अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करेंगे। न.दि.न.परिषद् के 27 स्कूल भवनों की छतों पर 1.7 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल की स्थापना का कार्य वित्त वर्ष 2015-16 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। यह कार्य 25 वर्ष की अवधि के लिए पावर क्रय अनुबंध के अंतर्गत किया जा रहा हैं।

भारत सरकार के पूंजी सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठान, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के माध्यम से नामांकन के आधार पर 1.5 मेगावाट क्षमता के रूफ-टॉप सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव है। इससे न.दि.न.परिषद् को नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्वों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी, जो डीईआरसी द्वारा वितरण कंपनियों के लिए आदेशित हैं। न.दि.

This will improve the efficiency and thereby reduce the energy consumption. For this purpose, ₹2.00 crore would be kept from the fund provisions for Smart City in the year 2016-17.

10 Smart Street Poles

On PPP model, it is proposed to transform existing 20,500 Sodium Vapour Lights/CFLs on 18500 electric Poles with Smart LED luminaries (having incident driven Controller and traffic analytics at major junctions and BQS), CCTV for City Surveillance, free Wi-Fi for 20 minutes at 512kbps to public in all major hotspots. The smart poles will have CCTV surveillance for Public safety and security. Successful Concessioner would make available their Communication network to NDMC to run its services. This Communication network will be used by the NDMC for its Smart City initiatives like Smart Education, Health, Energy Grid, Water Grid, Solid Waste Management and extending citizen services. The project would include setting up a Centralized Command and Control Centre in Palika Kendra.

In lieu of these services to NDMC, the Concessioner will be allowed free usages of ROW, use of Electric Poles and NDMC premises, wherever it is possible, for setting up network devices. Concession period will be of 15 years. As a policy change, the Concessioner would be allowed to restore the footpath and roads at its own cost. At present, restoration work is being done by NDMC.

11 Solar Energy

Exploration of new energy avenues is the need of the time, which is planned through rooftop solar panels at NDMC buildings to act as sustainable renewal energy source. The work of setting up of roof-top solar panel of capacity 1.7 MW on 27 NDMC school buildings would be completed by end of financial year 2015-16. This is under the power purchase agreement for a period of 25 years.

It is proposed to install 1.5 MW roof-top solar panels under capital subsidy programme of Government of India through Solar Energy Corporation of India, a central PSU, on a nomination basis. This will help NDMC in complying with the renewable energy purchase obligations as mandated by DERC for DISCOMs.

न.परिषद् के शेष भवनों की छतों पर अतिरिक्त रूफ-टॉप सोलर पैनल स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

दिल्ली सरकार/दक्षिण दिल्ली नगर निगम से भूमि प्राप्त करते हुए संयुक्त उद्यम के रूप में 10 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का प्रस्ताव किया जाता है। इस क्षेत्र के लिए स्मार्ट सिटी निधि प्रावधान में से वर्ष 2016-17 में ₹20 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

12. ई-गवर्नेंस

भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म में मोबाइल अप्लीकेशंस के व्यापक इस्तेमाल की व्यवस्था है। इसे देखते हुए न.दि.न.परिषद् के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव जो 15 दिसंबर, 2015 को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को सौंपा गया था, में ई-गवर्नेंस एक प्रमुख घटक है।

मैं, शासन को नागरिक उन्मुखी बनाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भरता बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अंतर्गत आईसीटी (सूचना संचार प्रौद्योगिकी) द्वारा, विशेषकर मोबाइल सेवाओं का इस्तेमाल करते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जाएंगे। इससे सेवाओं की लागत में कमी आएगी और सेवाएं प्राप्त करने के लिए म्युनिसिपल कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम होगी। ई-गवर्नेंस का लक्ष्य आंतरिक प्रक्रियाओं की री-इंजीनियरिंग द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जिससे कागज रहित संचार को बढ़ावा मिलेगा।

मैं, इस दिशा में निम्नलिखित उपाय लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ:-

(i) अबाधित डेटा विनिमय के लिए न.दि.न.परिषद् कार्यालयों की पी2पी नेटवर्किंग;
(ii) डेटा सेंटर का सुदृढ़ीकरण;
(iii) निगरानी संबंधी जीपीएस उपकरणों के लिए स्मार्ट विधियों का इस्तेमाल आदि;
(iv) नागरिकों की शिकायतों के निवारण, क्षेत्र निरीक्षणों, सेवाओं के वितरण आदि के लिए क्लाउड-आधारित स्मार्ट मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का विकास/खरीदना;
(v) बारातघरों, इवेंट मैनेजमेंट और अन्य सेवाओं की बुकिंग के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू करना।
(vi) बायोमेट्रीक उपस्थिति का विस्तार तथा पे-रोल प्रणाली के साथ इसको जोड़ना।

बजट अनुमान 2016-17 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए ₹7.20 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से ₹4.45 करोड़ पूँजीगत व्यय के लिए है।

Opportunities will be explored to establish additional roof-top solar panels on remaining NDMC buildings as per feasibility.

It is proposed to establish a 10MW solar power plant on getting land from the Delhi Government /South Municipal Corporation of Delhi as a joint venture. A provision of ₹20.00 crore has been kept out of Smart City fund provision for this sector in 2016-17.

12 e-Governance

The Digital India Programme of Government of India envisages extensive usage of mobile applications in e-Governance platform. e-Governance is the key component of Smart City Proposal of NDMC, which was submitted to the Ministry of Urban Development, Government of India on 15th December, 2015.

I am proposing to make governance citizen friendly with increased reliance on online services in order to bring accountability and transparency through ICT, especially by using mobiles to reduce cost of services, and providing services by minimising the need to visit municipal offices. e-Governance shall be achieved through re-engineering internal processes, and will encourage paperless communication.

I am proposing to implement the following in this regard:

(i) P2P networking of NDMC's offices for seamless data exchange;
(ii) strengthening of data centre;
(iii) use of smart devices for monitoring GPS devices etc.;
(iv) developing / subscribing to cloud-based smart mobile based applications for citizens' complaints redressals, field inspections, delivery of services etc.;
(v) implementing online payments for booking of barat ghars, event management and other services;
(vi) extension of Bio-metric Attendance and linking it with pay-roll system.

A provision of ₹7.20 crore has been kept for Information and Technology Services in BE 2016-17, out of which ₹4.45 crore is for capital expenditure.

13. सड़कें एवं पटरियाँ

हमारे परिचालन गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के क्रम में वर्ष 2015-16 के दौरान सीआरआरआई द्वारा मूल्यांकित 24 सड़कों में से 9 सड़कों का कार्य पूरा किया जाएगा। शेष 15 सड़कों को वर्ष 2016-17 के दौरान लिया जाएगा।

हम लोधी कालोनी, बी.के. दत्त कालोनी तथा अरविन्दो मार्ग में सड़कों के सशक्तिकरण का कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित करते हैं। बी.के.एस. मार्ग पर ब्लॉक 18-33 एवं सैक्टर-II, डी आई जेड क्षेत्र पर अंतर्योजक पटरियों की व्यवस्था एवं लगाकर तथा सरोजिनी नगर, पिलंजी गाँव में जल निकासी प्रणाली एवं आर एम सी द्वारा विद्यमान सड़कों के सुधार का कार्य वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।

बजट अनुमान 2016-17 में सड़कों एवं पटरियों के लिए ₹132.42 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है तथा ₹42.94 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए है।

14. स्मार्ट पार्किंग

116 विद्यमान पार्किंग स्थलों को पीपीपी मॉडल पर केन्द्रीय मोबाइल आधारित स्मार्ट पार्किंग प्रबंधन प्रणाली के साथ लिंक करके सेन्सर आधारित पार्किंग स्थलों में परिवर्तित किया जाएगा। नागरिकों को खाली पार्किंग स्थल का पता लगाने में मदद करने के लिए मोबाइल एप की शुरूआत की जाएगी। केन्द्रीयकृत पार्किंग डाटाबेस न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में प्रभावकारी पार्किंग योजना पर इनपुट देने तथा जन साधारण को वास्तविक समय पर पार्किंग उपलब्धता के प्रसार में मदद करेगा। इससे पार्किंग को लोगों के अनुकूल बनाने में दीर्घावधि लाभ मिलेगा।

15. भूमिगत मार्गों को एटीएम और सिग्नेचर विज्ञापन पैनलों की व्यवस्था के साथ सशक्त स्थलों के रूप में परिवर्तित करना

कनाटप्लेस क्षेत्र में 7 भूमिगत मार्गों में फुटफाल्स में सुधार लाने के लिए यह प्रस्ताव है कि इन भूमिगत मार्गों में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्थान दिया जाए ताकि वे नाम मात्र के शुल्क पर नामांकन आधार पर ई-बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकें।

16. द्वि-शहर यानी ट्विन सिटी अनुबंध

वैश्विक शहरों के साथ सहयोग और संपर्क कायम करने के लिए, मैं, भारत सरकार से परामर्श पश्चात्, अंतरराष्ट्रीय शहरों के साथ द्वि-शहर यानी ट्विन सिटी अनुबंध का प्रस्ताव करता हूँ। न.दि.न.परिषद् और अन्य वैश्विक शहरों के बीच इस तरह के द्वि-शहर अनुबंध से सूचना, विचारों, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और अन्य संगत गतिविधियों के आदान प्रदान में मदद मिलेगी।

13 Roads & Pavements

In continuation of our Riding Quality Improvement Programme, 9 roads out of 24 roads evaluated by CRRI shall be completed during the year 2015-16. The remaining 15 roads shall be taken up during the year 2016-17.

We propose to undertake re-surfacing of roads in Lodhi Colony, B K Dutt Colony and Aurbindo Marg. The work of improvement to existing roads by providing RMC & drainage system in Pillanji Village, Sarojini Nagar; providing & fixing inter-locking pavers at Sector II, DIZ area & Block 18-33 at BKS Marg shall be taken up in 2016-17.

A provision of ₹132.42 crore has been kept for Roads and Pavements in BE 2016-17, out of this, ₹42.94 crore is for capital expenditure.

14 Smart Parking

116 existing parking spaces would be converted into sensor-based parking spaces linked with a centralized mobile-based Smart Parking Management System on PPP model. Mobile App will be introduced to help citizens to locate a vacant parking space. Centralised parking database will help in disseminating real-time parking availability to public and giving inputs on effective parking planning in NDMC area. This would go a long way in making parking people friendly.

15 Transforming Sub-ways into vibrant spaces with ATMs and signature advertising panels

To improve the foot-falls in the 7 sub-ways in the Connaught Place area, it is proposed to offer space in these sub-ways only to Public Sector Banks for setting up e-banking facilities on nomination basis at a token fee.

16 Twin-city Agreements

To facilitate cooperation and linkages with global cities, I propose to sign twin cities agreements with international cities, in consultation with the Government of India. Such Twin City Agreements would facilitate exchange of information, ideas, technical assistance, training and other pertinent activities related to city agreement between NDMC and other global cities.

17. इन्क्यूबेशन सेंटर

इन्क्यूबेशन सेवाएं उन सुविधाओं का नाम है, जो उद्यमियों को पर्याप्त परिपक्व होने तक उनके विचार विकसित करने में मदद पहुंचाती हैं ताकि वे अपने में आत्मनिर्भर बन जाएं या उनकी वाणिज्यिक सशक्तता दिखाई देने लगे। इससे वे उद्यम पूंजीपतियों/निवेशकों से धन आकर्षित कर सकेंगे। इन्क्यूबेटर सेवाओं में प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस से लेकर निगरानी, परामर्श और सीड फंडिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं।

व्यापार इन्क्यूबेशन उद्यमिता कंपनियों के विकास को बढ़ावा देते हैं वे उन्हें प्रारंभिक अवधि में उस समय अस्तित्व बनाए रखने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जब वे सर्वाधिक कमजोर स्थिति में होते हैं।

व्यापार इन्क्यूबेटर नए प्रौद्योगिकी उन्मुखी उद्यमियों और उनकी फर्मों को विकास के प्रारंभिक दौर में सहायता पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत कार्यस्थल प्रदान करना, साझा सुविधाएं तथा कई तरह की व्यापार सहायता सेवाएं प्रदान करना शामिल है। आज जो व्यापार इन्क्यूबेट किए जा रहे हैं, वे नवीन एवं नवरूप प्रौद्योगिकियों के विकास, उत्पादों और सेवाओं के सृजन में अग्रणी हैं, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पिछले दो दशकों से आईटी उद्योग के विकास का केंद्र बन रहा है। हाल के वर्षों में यह देखा जा सकता है कि उद्यमशीलता की संस्कृति और नया उद्यम शुरू करने की प्रवृत्ति भारत में लोकप्रिय होती जा रही है और अधिकाधिक नए व्यवसायी, नए स्नातक और अनुभवी व्यक्ति नए क्षेत्रों में उद्यमशीलता विकसित कर रहे हैं।

मांग और भावी संभावनाओं को देखते हुए मैं मयूर भवन में 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र में आईटी उद्योग के लिए एक इन्क्यूबेटर की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं ताकि नए विचार रखने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए इन्क्यूबेशन सेवाओं के लिए पूर्ण स्थान प्रदान किया जा सके।

यह प्रस्ताव है कि न.दि.न.परिषद् इस परियोजना में साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क्स आफ इंडिया (एसटीपीआई) (इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त समिति) के साथ भागीदार बने, क्योंकि एसटीपीआई के पास देश में इन्क्यूबेशन सेवाएं प्रदान करने का व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है।

इस सुविधा के विकास पर 5 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

17 Incubation Centre

Incubation services are the facilities which help entrepreneurs to develop their ideas till they are mature enough to either sustain themselves or their commercial viability is visible thereby enabling them to attract funding from venture capitalists / angel investors. Incubator services can range from plug & play office space to mentoring, advisory as well as seed funding.

Business incubation nurtures the development of entrepreneurial companies, helping them survive and grow during the start-up period, when they are most vulnerable.

Business incubators can assist technology-oriented entrepreneurs in the start-up and early development stage of their firms by providing workspace, shared facilities and a range of business support services. The businesses being incubated today are at the forefront of developing new and innovative technologies, creating products and services that improve the quality of our lives.

The National Capital Region has been a hotbed of the growing IT industry over the last two decades. In the recent past, it can be seen that the culture of entrepreneurship and start-ups is fast becoming popular in India and more & more professionals, fresh graduates as well as experienced ones are treading uncharted territories.

Keeping in view of the demand and future prospects, I propose to establish an Incubator for the IT industry in Mayur Bhawan in 10000 sq. ft. to provide complete suite of incubation services to individuals/entities having innovative ideas for a maximum period of 2 years.

It is proposed that NDMC may partner with Software Technology Parks of India (**STPI**) (an autonomous society under Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology) for this project as STPI has requisite expertise in providing incubation services across the country.

An estimated cost of ₹5 crore shall be incurred for developing the facility.

18 वाणिज्यिक विकास परियोजनाएँ

नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए, ₹50 करोड़ की लागत पर, निर्मित क्षेत्र 8000 वर्ग मीटर के साथ यशवंत प्लेस में एक वाणिज्यिक काम्पलैक्स तथा ₹38.29 करोड़ की लागत पर पंचकुइयाँ रोड स्थित बापू समाज केन्द्र को पुन:विकसित करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु बजट अनुमान 2016-17 में ₹10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

19 म्युनिसिपल मार्किट

मोहन सिंह प्लेस, पालिका प्लेस तथा लोकनायक भवन पर सुधार कार्य, जो पिछले वर्ष प्रारम्भ किया गया था, पूर्ण हो गया है। मयूर भवन में कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा, जबकि, पालिका प्लेस में आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है। बजट अनुमान वर्ष 2016-17 में म्युनिसिपल मार्किटों हेतु ₹33.96 करोड़ का प्रावधान रखा है जिसमें से पूंजीगत व्यय हेतु ₹14.40 करोड़ है।

20 कर्मचारी कल्याण

हमने 'जीवन प्रमाण डिजीटल लाइफ सर्टिफिकेट' को लागू किया है, जो हमारे पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रत्यक्ष प्रस्तुत होने की असुविधा तथा कठिनाईयों को कम करेगा। न.दि.न.परिषद् के कर्मचारियों को सेवानिवृति के सभी सावधिक हितलाभ सेवानिवृति उपरांत आगामी मास के प्रथम कार्यदिवस पर इलैक्ट्रोनिक मोड द्वारा कर्मचारियों के एकाउंट में भुगतान/क्रेडिट किए जा रहे हैं। हमने ईपीएफओ के लिए नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के ईपीएफ अंशदान की कटौती एवं धन प्रेषण हेतु ईपीएफ माड्यूल लागू किया है।

हम अपने आरएमआर तथा टीएमआर कर्मचारियों हेतु दो कल्याणकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करते हैं। इस प्रयोजन हेतु बजट अनुमान वर्ष 2016-17 तथा संशोधित अनुमान 2015-16 प्रत्येक में ₹25 लाख का प्रावधान है।

21 म्युनिसिपल कर्मचारियों हेतु आवास

म्युनिसिपल कर्मचारियों के आवास हेतु संतोषजनक स्तर में सुधार के लिए ₹211 करोड़ की लागत पर अर्जुन दास कैम्प पर टाइप-IV एवं V के 336 विशेष फ्लैट तथा ₹45 करोड़ की लागत पर साकेत के सेक्टर-7 में टाइप-II के 120 फ्लैट ₹82 करोड़ की लागत पर साकेत सेक्टर-6 में टाइप-III के 160 फ्लैट, ₹47.34 करोड़ की लागत पर अलीगंज में टाइप-II के 188 फ्लैटों के निर्माण की योजना है। राजीव आवास योजना के अंतर्गत सराय काले खां नई दिल्ली में ₹150 करोड़ की लागत पर स्लम डेवेलर्स हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवासीय ईकाई के 1200 फ्लैट के निर्माण की योजना है। आशा की जाती है कि अलीगंज, सेक्टर-6, साकेत तथा

18 Commercial Development Projects

To ensure the regular income, it is proposed to redevelop Bapu Samaj Kendra at Panchkuian Road at a cost of ₹38.29 crore and a Commercial Complex at Yashwant Place with built up area of 8000 square meters at a cost of ₹50 crore. For this purpose, provision of ₹10 crore has been kept in the B.E. 2016-17.

19 Municipal Markets

Improvement works at Mohan Singh Place, Palika Place & Lok Nayak Bhawan, which were taken up last year, have been completed. In Mayur Bhawan, the work shall be completed by the end of current financial year itself, whereas in Palika Place the work is likely to be completed in first quarter of next financial year. A provision of ₹33.96 crore has been kept for Municipal Markets in BE 2016-17 out of which ₹14.40 crore are for capital expenditure.

20 Employees' Welfare

We have implemented the 'Jeevan Pramman Digital Life Certificate' to mitigate the inconvenience of our pensioners who have to physically present for submission of life certificate every year. All retirement terminal benefits to NDMC employees are now being paid/ credited in the accounts through electronic mode on the first working day of the ensuing month after retirement. We have implemented an EPF Module for deduction and remittance of EPF contribution - of both, employer and employee, to EPFO.

We propose to introduce two welfare schemes, namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna for our RMR and TMR workers. A provision of ₹25 lacs each in revised estimates 2015-16 and budget estimates 2016-17 has been kept for this purpose.

21 Housing for Municipal Employees

To improve satisfaction level of housing to Municipal employees, it is planned to construct 188 Type-II Flats at Aliganj at a cost of ₹47.34 crore, 160 Nos. Type-III Flats at Sector-VI Saket at a cost of ₹82 crore, 120 Type-II Flats at Sector-VII Saket at a cost of ₹45 crore, and 336 Type-IV & Type-V Special Flats at Arjun Dass Camp at a cost of ₹211 crore. It is planned to construct 1200 Nos. EWS dwelling units for Slum dwellers at a cost of ₹150 crore at Sarai Kale Khan, New Delhi under Rajiv Awas Yojana.

सेक्टर-7 साकेत के संबंध में वर्ष 2016-17 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा अपेक्षित वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। इसलिए, इन परियोजनाओं पर वर्ष 2016-17 में कार्य आरंभ किया जा सकेगा। म्युनिसिपल हाउसिंग परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय हेतु वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में ₹23.23 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया।

22. जमीनी स्तर के म्युनिसिपल कर्मचारियों का सशक्तिकरण

जमीनी स्तर पर न.दि.न.परिषद् कर्मचारियों के सशक्तिकरण के लिए न.दि.न.परिषद् ने सफाई कर्मचारियों और बेलदारों को 23 नवम्बर से 28 नवम्बर 2015 की अवधि में टोकियो और सोल में तथा बागवानी विभाग के मालियों और चौधरियों को 4 जनवरी से 8 जनवरी, 2016 की अवधि में सिंगापुर भेजा ताकि वे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियों की जानकारी प्राप्त कर सकें। इससे, हमारी कार्य संस्कृति में अपेक्षित बदलाव आएगा और न.दि.न.परिषद् वास्तव में एक वैश्विक राजधानी शहर बन सकेगा।

मैं, वर्ष 2016-17 में ऐसी पद्धतियों को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ इसके अंतर्गत निचले स्तर के कर्मचारियों को अन्य अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भेजा जाएगा। बजट अनुमानों 2016-17 में इसके लिए ₹50 लाख रखे गये हैं।

23. एक आधुनिक पशु चिकित्सालय या तो चरक पालिका अस्पताल के समीप मोती बाग अथवा सरोजिनी नगर में पुलिस स्टेशन के समीप न.दि.न.परिषद् भूमि पर सभी अपेक्षित सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा बजट अनुमान 2016-17 में ₹5 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

24 प्राप्तियाँ

24.1 विद्युत वितरण से प्राप्तियाँ

पावर सेक्टर की समग्र वित्तीय स्थिति के सशक्तिकरण के क्रम में, न.दि.न.परिषद् ने मंहगे पावर वितरण स्टेशनों से मंहगी पावर क्रय के बजाय पावर एक्सचेंजों से अधिकतम लगभग 60 मेगावाट, सस्ती पावर क्रय करना आरम्भ किया है।

अक्टूबर 2015 के बाद से, न.दि.न.परिषद् ने वर्ष 2014-15 की अनुवर्ती अवधि की तुलना में इस कार्यनीति के कारण लगभग ₹110 करोड़ की बचत की हैं। परिणामस्वरूप राजस्व हानि वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कम होगी।

विद्युत वितरण से कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2014-15 के वास्तविक आंकड़ों ₹1097.54 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 में संशोधित अनुमान ₹1132.32 करोड़ अनुमानित किया गया है। बजट अनुमान वर्ष 2016-17 में अनुमान ₹1131.93 करोड़ है- लगभग ₹39 लाख की छोटी

It is expected that the Detailed Project Report and requisite statutory clearances would be completed in 2016-17 with respect to Aliganj, Sector VI Saket and Sector VII Saket. Therefore, work would start on these projects in the year 2016-17. A provision of ₹23.23 crore has been proposed in the B.E. of 2016-17 for capital expenditure on municipal housing projects.

22 Empowering the grass-root municipal officials

In order to empower NDMC officials at grass-root level, NDMC has deputed Safai Karamcharis and Beldars to Tokyo and Seoul from 23rd November to 28th November 2015 and Malis and Chaudhris of Horticulture Department to Singapore from 4th January to 8th January, 2016 to give them exposure to the global best practices which would bring requisite changes in our work culture to make NDMC truly global capital city.

I propose to institutionalize such practices in the year 2016-17 by deputing grass-root level officials to other International cities for which a provision of ₹50 lacs has been kept in the BE 2016-17.

23 A modern Veterinary Hospital would be developed with all requisite facilities either near the Charak Palika Hospital, Moti Bagh, or in Sarojini Nagar on NDMC land near Police Station. A provision of ₹5 crore has been kept in the Budget Estimates 2016-17.

24 Receipts

24.1 Receipts from Electricity Distribution:

In order to strengthen the overall financial position of the Power sector, NDMC has embarked on purchasing cheaper power to the extent of about 60 MW from power exchanges instead of buying expensive power from the costly power generating stations.

Since October 2015, NDMC has saved about ₹110 crore on account of this strategy compared to the corresponding period of 2014-15. As a result revenue loss would be lowered in 2015-16 as compared to 2014-15.

The total revenue receipts from Electricity Distribution have been projected in RE 2015-16 at ₹1132.32 crore as against Actuals 2014-15 of ₹1097.54 crore. The projections for BE 2016-17 are at ₹1131.93 crore - a small reduction of only ₹39 lakhs despite abolition

सी कटौती है जोकि डीईआरसी द्वारा पिछले संचित घाटे की वसूली हेतु अतिरिक्त अधिभार के उन्मूलन के बावजूद है जिस पर हमने चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹52 करोड़ प्राप्त किए हैं।

24.2 सम्पत्ति कर से प्राप्तियाँ

हम हमारे सम्पत्ति कर संग्रहण को लगातार बढ़ा रहे हैं। मुझे यह रिपोर्ट देते हुए प्रसन्नता हो रही हैं कि हमने वर्ष 2014-15 में सम्पत्ति कर संग्रहण हेतु ₹370 करोड़ के हमारे लक्ष्य का 99. 96 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। हम संशोधित अनुमान 2015-16 में ₹400 करोड़ तथा बजट अनुमान 2016-17 में ₹465 करोड़ के सम्पत्ति कर संग्रहण हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने दायरे को बढ़ा रहे है। मैं वर्ष 2016-17 हेतु सम्पत्ति कर दरों में किसी प्रकार की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ।

यद्यपि, मैं सम्पत्ति कर निर्धारण तथा उसकी वसूली को सुप्रवाही बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं वर्ष 2016-17 में सभी लंबित निर्धारण आदेशों को स्पष्टत: अन्तिम रूप देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं सम्पत्ति कर रिटर्न को फाईल करने हेतु ऑनलाइन पद्धति को आरम्भ करना भी प्रस्तावित करता हूँ।

24.3 नगरपालिका सम्पत्तियों से लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियाँ

वर्तमान में बड़ी संख्या में न.दि.न.परिषद् सम्पत्तियाँ, जोकि लाइसेंस पर है, नीति निर्णयों के अभाव में नवीकरण/स्थानातरण हेतु प्रतीक्षारत है। इसलिए माननीय परिषद् ने अपनी दिनांक 15.12.2015 की बैठक में इस संबंध में सुझाव, परामर्श तथा नीति तैयार करने हेतु न.दि.न. परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 9 के अन्तर्गत समिति गठित की है। एक बार नीति तैयार हो जाती है तो लाइसेंस प्राप्त नगरपालिका सम्पत्तियों के संबंध में प्राप्तियों में वृद्धि होगी। परिषद् द्वारा ऐसी नीति निर्धारण लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं के सामने आ रही कठिनाइयों को कम करेगी। इस पद्धति में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु, नगरपालिका की ऐसी सम्पत्तियों के सभी रिकार्ड इलैक्ट्रोनिकली रखे जाएगें।

लाइसैंस की शर्तो का दुरूपयोग अथवा उल्लंघन से बचाव के लिए वर्ष में कम से कम एक बार इन सम्पत्तियों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सिविल, विद्युत, उद्यान, जन-स्वास्थ्य तथा वास्तुविद् विभाग से अधिकारियों द्वारा अपेक्षित संख्या में समर्पित टीमों के गठन का भी प्रस्ताव है।

म्युनिसिपल सम्पत्तियों से लाइसैंस शुल्क हेतु संशोधित अनुमान 2014-15 में ₹391.25 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2014-15 में वास्तविक प्राप्तियाँ ₹438.80 करोड़ है। वर्ष 2015-16 संशोधित अनुमान ₹457.45 करोड़ तथा बजट अनुमान वर्ष 2016-17 में ₹523.09 करोड़ है।

of additional surcharge for recovery of past accumulated losses by the DERC on which account we received ₹52 crore in current financial year 2015-16.

24.2 Receipts from Property Tax

We are steadily increasing our Property Tax collections. I am happy to report that we have achieved 99.96% of our target of ₹370 crore for Property Tax Collection in 2014-15. We are raising the bar for ourselves by fixing the target for collection of Property Tax at ₹400 crore in RE 2015-16 and ₹465 crore in BE 2016-17. I am not proposing any increase in Property Tax rates for the year 2016-17.

However, I am proposing to streamline the assessment of property tax and its realization. I am proposing to finalize all pending assessment orders in the year 2016-17. I am proposing to introduce an online system for filing of property tax returns in the year 2016-17.

24.3 Receipts from Licence Fee from Municipal Properties

At present, large number of NDMC properties, which are on licence, are awaiting renewal/transfer for want of policy decisions. Therefore, Hon'ble Council in its meeting held on 15.12.2015 constituted a Committee under section 9 of the NDMC Act 1994 to suggest, guide and frame a policy in this regard. Once the policy is in place, the receipt in respect of licensed municipal properties will increase. Framing such a policy by the Council will reduce the hardships being faced by the licensees. To ensure transparency in this system, it is proposed to store all the records of such municipal properties electronically.

It is also proposed that requisite number of dedicated teams will be formed by drawing officials from Civil, Electrical, Horticulture, Public Health and Architect Department to ensure inspection of all such properties at least once in a year, to avoid misuse or violation of the licence conditions.

The actual receipts in 2014-15 for Licence Fee from municipal Properties stood at ₹438.80 crore against the target of ₹391.25 crore in RE 2014-15. The projections for RE 2015-16 are at ₹457.45 crore and BE 2016-17 are at ₹523.09 crore.

माननीय सदस्य, वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, किन्तु हम मजबूत एवं वित्तीय रूप से स्थायी संगठन के रूप में सत्त रहने हेतु दृढसंकल्प है जो नागरिकों के लिए किए गए प्रत्येक कार्य में उन्हें प्रमुखता देती हैं। इसे सफल बनाने के लिए हमें निरंतर समर्पण तथा टीमवर्क के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगामी वर्ष अपनी चुनौतियां लाएगा किन्तु मुझे विश्वास है कि एक साथ कार्य करते हुए अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तथा अपने ग्राहकों को सर्वप्रथम रखते हुए हम अपने लक्ष्यों को साकार कर सकते हैं।

अंतिम लेकिन कम नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय संसद सदस्य, परिषद् के उपाध्यक्ष, माननीय विधायक तथा परिषद् के गणमान्य सदस्यों को उनके निरन्तर सकारात्मक सहयोग तथा समय-समय पर मुझे दिए गए उनके अमूल्य सुझावों हेतु धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं माननीय गृहमंत्री, गृह मंत्रालय, माननीय शहरी विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय तथा माननीय उपराज्यपाल दिल्ली से प्राप्त मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए आभार प्रस्तुत करना चाहूँगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

जय हिन्द!

Hon’ble Members, the targets proposed for the year 2016-17 are challenging, but we are determined to continue as a strong and financially sustainable organization that puts the citizen at the heart of everything it does. We need to move forward with continued dedication and teamwork to make it a success. The year ahead will bring its own challenges but I am sure that, by working together, staying focused on our priorities and putting our customers first, we can realize our targets.

Last but not the least, I would like to thank Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Member of Parliament, Vice-Chairman of the Council, Hon'ble MLA and distinguished Members of the Council for their continued constructive support and invaluable suggestions extended to me from time to time. I would like to place on record my gratitude for the guidance and support received from Hon'ble Home Minister, Ministry of Home Affairs, Hon’ble Urban Development Minister, Ministry of Urban Development, and Hon’ble Lieutenant Governor of Delhi.

Thank you very much.

Jai Hind.